स्वच्छ भारत
सम्पूर्ण स्वच्छता की ओर

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

स्वच्छता समाचार

जनवरी 2024

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण न्यूज़लेटर

@swachhbharat @SBMGramin @SwachhBharatMissionGramin @swachh_bharat @swachhbharatgrameen

"अपने गांव, अपने पड़ोस और अपने शहर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने का काम करें।"

18 दिसंबर 2023 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्वर्वेद मंदिर के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन

श्री नरेन्द्र मोदी
भारत के प्रधानमंत्री

"चूंकि 2023 समाप्त हो रहा है, अत: यह समय पिछले 12 महीनों में हमारी जल, स्वच्छता और साफ-सफाई की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें प्रतिबिंबित करने तथा नव वर्ष के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने का है। लाइटहाउस पहल और रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम के साथ हमारी कार्यनीतिक भागीदारी एक उल्लेखनीय कदम रहा है क्योंकि विकास कार्यों से जुड़े सहयोगियों और कॉर्पोरेट घरानों की विभिन्न ODF-Plus गतिविधियों को क्रियान्वित करने में सहयोग रहा है। हमारा देश वास्तव में 2025 तक SBM-G चरण-II लक्ष्यों को हासिल करने के मार्ग पर है और एक ऐसे देश के हमारे दृष्टिकोण को एक वास्तविकता बना रहा है जहां हर व्यक्ति की सुरक्षितय शौचालय और बेहतर स्वच्छता तक पहुंच हो।"

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

स्वच्छता समाचार

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

28 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार

ODF PLUS

भारत के 5,12,598 से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF-Plus घोषित किया है।

- **उज्जवल: 3,21,539**
- **उदीयमान: 61,930**
- **उत्कृष्ट: 1,29,129**

2,75,180 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित
4,41,413 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित
1,150 बायोगैस संयंत्र पंजीकृत
642 कार्यात्मक बायोगैस स्थापित
123 पूर्ण बायोगैस स्थापित
2,981 प्रखंडों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां स्थापित

स्वच्छता पखवाड़ा

रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने 01 से 15 दिसंबर, 2023 तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के बाजारों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पार्कों में स्वच्छता अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विद्यालयों में स्वच्छता के महत्व पर बच्चों के मध्य निबंध लेखन प्रतियोगिताएं हुईं। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए, HAL आवासीय कॉलोनियों और कार्यालय इकाइयों के विभिन्न टाउनशिप में फ्यूमिगेशन किया गया था। हैदराबाद, कानपुर और बेंगलुरु में HAL कार्यालयों और विद्यालयों में सुरक्षित स्वच्छता के महत्व पर सेमिनार आयोजित किए गए।

HAL के मुख्य गेट से सिंधिया जंक्शन तक प्लॉगिंग का आयोजन किया, जिसमें 100 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया, जबकि मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने भी एक प्लॉगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया।

कृषि और किसान कल्याण; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी; और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयों में भी 16 से 31 दिसंबर, 2023 तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया।

JJM और SBM-G महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, आर्थिक अवसर प्रदान करते हैं: संयुक्त सचिव व मिशन निदेशक

संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर से 12 दिसंबर, 2023 तक आयोजित COP 28 के साइड इवेंट्स में एक विषय 'महिला और जल' था। इस कार्यक्रम में, पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) तथा जल जीवन मिशन (JJM) के तहत उपलब्धियों को प्रस्तुत करने, वॉश के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देने और भारत में महिलाओं के जीवन में दोनों प्रमुख कार्यक्रमों की उपलब्धियों और प्रभाव को प्रकटित करने का अवसर मिला।

इस अवसर पर आयोजित वार्ता में, श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक (JS & MD) ने कहा कि JJM ने COP 28 के जलवायु लचीलापन के लक्ष्यों की समंजस्यता में जल क्षेत्र में निर्णयक के रूप में महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

JJM के परिणामों में बेहतर स्वास्थ्य, समय की बचत, शिक्षा के अवसर, पानी भरकर लाने की चिंता को कम करना, जीवन जीने में आसानी, आत्मविश्वास विकास, भागीदारी में वृद्धि, जल गुणवत्ता परीक्षण में पर्याप्त प्रशिक्षण और नए आर्थिक अवसर शामिल हैं।

दूसरी ओर, SBM-G चरण-II में महिलाओं को नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है क्योंकि उन्हें शौचालयों के निर्माण और रखरखाव जैसे नए कौशल में प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह लिंग भेद को मिटाने और अधिक न्यायसंगत समाज बनाने में मदद कर रहा है।

मिशन के चरण-II का उद्देश्य स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके देश की समग्र स्वच्छता तथा साफ-सफाई में सुधार लाना है। JS & MD ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं, जो महिलाओं द्वारा प्रबंधित और अनुरक्षित की जा रही हैं, महिलाओं को स्थिर आय प्रदान कर रही हैं और उनके समुदायों में समग्र स्वच्छता में सुधार लाने में मदद कर रही हैं।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्रणाली पर चर्चा के लिए राज्यों के पर्यटन सचिवों की बैठक

स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम (SGLR) जिसे 02 नवंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) द्वारा शुभारंभ किया गया था, को 28 से 29 नवंबर, 2023 के बीच राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित राज्य पर्यटन सचिवों की बैठक में शुरू किया गया।

यह प्रणाली जो सुरक्षित स्वच्छता व्यवहारों के अनुपालन के आधार पर देश की आतिथ्य सुविधाओं को रेट करेगी, नीति आयोग के मिशन LiFE के तहत पर्यटन मंत्रालय की 'जीवन के लिए यात्रा' प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

रेटिंग प्रणाली की शुरूआत संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर से की गई है और इसके बाद इसकी राष्ट्रव्यापी शुरूआत की जाएगी। यह देखते हुए कि यह एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहां सबसे अधिक संख्या में बार-बार पर्यटक आते हैं, अत: यह सुरक्षित स्वच्छता के क्षेत्र में दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा।

DDWS और पर्यटन मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में रेटिंग प्रणाली के अग्रणी कार्यान्वयन के लिए एक प्रस्तावना तथा मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में एक संयुक्त नीति दस्तावेज तैयार किया गया है।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

कबाड़ से जुगाड़ - बलरामपुर मतदान केंद्र का विषय

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की भनौरा ग्राम पंचायत में स्थित मतदान केंद्र संख्या 216 छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए चुनावों के दौरान चर्चा का विषय था। यह जिले की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) टीम द्वारा रबर, कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़े और लकड़ी के स्क्रैप बिट्स से बनाया गया था, जो यह दर्शाता है कि अगर कचरे को ठीक से प्रबंधित किया जाए तो इसे संसाधन के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।

स्वच्छाग्रहियों की मदद से एक प्राथमिक विद्यालय में मतदान केंद्र 216 स्थापित किया गया था। जिला पंचायत CEO सुश्री रेना जमील के मार्गदर्शन में स्थापित यह कार्यक्रम मतदाताओं के लिए आकर्षण का केंद्र था, जिसका विषय 'कबाड़ से जुगाड़' था। लोगों ने घर पर संदेश दिया कि कचरे का पुन:उपयोग करने से लैंडफिल में जाने वाले कचरे को कम किया जा सकेगा और आसपास की स्वच्छता सुनिश्चित होगी।

इस अभिनव पहल ने पर्यावरण की रक्षा के लिए पुनर्चक्रण और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर अंकुश लगाने के महत्व पर सभी मतदाताओं के लिए एक आंख खोलने के रूप में कार्य किया।

विधानसभा चुनाव 2023 से पहले, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में अद्वितीय मतदान केंद्र बनाने का निर्देश दिया।

ECI के निर्देशों के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ में बलरामपुर के जिला कलेक्टर, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी थे, श्री रेमिजेयुस एक्का जिले के सभी 12 मतदान केंद्रों को अद्वितीय कृतियों में बनाने के इच्छुक थे, जो जिले की भौतिक संरचना, संस्कृति, पर्यावरण, पर्यटन और दर्शनीय स्थलों, हरियाली और कृषि को दर्शाते हों।

मतदान केंद्र 216 का निर्माण कचरे का उपयोग करके बनाया गया था। चित्रित नारियल के गोले का उपयोग गुलदस्ते के लिए फूलदान के रूप में किया गया था जो मतदान केंद्र की खिड़की की सिल्लियों को सजाते थे। इसके अलावा, साफ, मरम्मत और पेंट किए गए ट्रैक्टर के टायरों ने मतदाताओं के लिए अपनी तस्वीरें खींचने के लिए एक रंगीन सेल्फी ज़ोन बनाया, जो चुनावों में उनकी भागीदारी को दर्शाता है, संदेश यह है - कचरे का उपयोग करके जीवन को रंगीन बनाया जा सकता है। चुनाव का लोगो कागज, प्लास्टिक के कटोरे प्लेटों, डिस्पोजेबल CD कैसेट, प्लास्टिक बॉल, बैडमिंटन रैकेट और कोक की बोतलों का उपयोग करके बनाया गया था। इसके अलावा मतदान केंद्र पर मतदाताओं के बैठने के लिए पीने के पानी के साथ में बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी।

मतदान केंद्र के बाहर, CCTV कैमरा लकड़ी का बना था और कांच की चूड़ियों से एक झूमर बना था। 100 प्रतिशत मतदान का आह्वान करने वाली वॉल पेंटिंग भी थीं। कूड़ेदान, एक प्लास्टिक बैंक ने एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध और भारत को कचरा मुक्त बनाने की आवश्यकता का संकेत दिया।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क: rajeshkjain1982@gmail.com

स्वयं को ODF Plus Model घोषित करने के लिए मिज़ोरम की कार्य प्रणाली

मिजोरम के 11 जिलों में से, मामित, कोलासिब, सेरछिप और हनाथियाल जिलों ने ODF Plus Model जिलों के रूप में असाधारण प्रदर्शन किया है। जबकि अधिकांश सफलता का श्रेय श्रमदान जैसी गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को दिया जाता है, अभिनव IEC गतिविधियों ने जिलों को ODF Plus Model जिलों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जिला समन्वयकों, स्वच्छाग्रहियों और गैर-सरकारी संगठनों ने भी ODF Plus Model की श्रेणी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके समन्वित प्रयास के पीछे सभी गतिविधियों के प्रेरणा शक्ति रहे हैं।

मिज़ो लोगों में सामुदायिक भागीदारी की एक मजबूत परंपरा होती है जैसा कि उन्होंने श्रमदान के दौरान प्रदर्शित किया है - एक आम प्रथा यह है कि जब वे सार्वजनिक स्थानों को साफ करते हैं और उसे बनाए रखते हैं तो उनमें एकजुटता होती है।

ODF Plus Model श्रेणी करने के लिए, जिला स्तरीय अधिकारियों ने कार्यान्वयन के लिए एक रूट मैप बनाने से पहले प्रत्येक ब्लॉक के लिए विस्तृत योजनाएं और लक्ष्य स्थापित किए। विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करने के अलावा, उन्होंने ODF Plus घटकों से संबंधित सूचना का प्रसार किया और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का आयोजन किया। शौचालयों तक 100% सुविधा सुनिश्चित करना; ठोस कचरा प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक खाद गड्ढे, और गदंला जल प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक सोख्ता गड्ढे; IHHL और CSC का निर्माण शुरू किया गया था; उन्होंने ODF Plus परियोजनाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्वच्छाग्रहियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया, उनके कार्य पूरा होने के लिए एक समय सीमा तय करते हुए, सोख्ता गड्ढे, खाद गड्ढे आदि के निर्माण के लिए अग्रिम धनराशि की पेशकश की।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क: mdsbmg.miz@gmail.com

राजस्थान में शहरी MRF में ग्रामीण क्षेत्रों से ठोस कचरे का सह-उपचार

पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार ने 23 अक्टूबर, 2023 को शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न प्लास्टिक कचरे सहित ठोस कचरे को मौजूदा शहरी सुविधाओं में उपचारित किया जा सकता है जो 15 किमी के दायरे में स्थित हैं।

वर्तमान में, राजस्थान में ULB के तहत 137 कार्यात्मक सामग्री रिकवरी सुविधाएं (MRF)/प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयां (PWMU) हैं, जिनमें से 61 में सह-उपचार के लिए अतिरिक्त क्षमता है। इन सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज विभाग के साथ आवश्यक समन्वय किया गया।

अभिसरण के माध्यम से, राजस्थान के 29 जिलों के 66 ब्लॉकों के लगभग 2,450 गांवों को ULB के 61 MRF/PWMUs से लाभ होगा।

यह पहल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS), भारत सरकार द्वारा 14 सितंबर, 2021 को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी क्षेत्रों के मौजूदा MRF/PWMUs का उपयोग करने के लिए जारी की गई सलाह को ध्यान में रखते हुए की गई है।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क: sbmg2018@gmail.com

स्वच्छता समाचार

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) स्मारकों की स्वच्छता प्रतियोगिता

देश भर में निर्विवाद रूप से बनाए गए पर्यटन स्थलों की पहचान करने और उत्सव मनाने के लिए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने एक स्वच्छता प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें सभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) स्मारकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

यह प्रतियोगिता असाधारण रूप से स्वच्छ और सुव्यवस्थित रूप से बनाए गए पर्यटक स्थलों को पहचान दिलाने और सम्मानित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसे 19 नवंबर, 2023 को विश्व विरासत सप्ताह के दौरान लॉन्च किया गया था।

DDWS ने एक व्यापक जांच सूची तैयार की है जिसमें सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, पर्याप्त शौचालय सुविधाएं, हैंडवाशिंग स्टेशन, सीवेज और मलीय कचरे के सुरक्षित निपटान, स्रोत पर ठोस कचरे का पृथक्करण, मार्गों की सफाई, कचरे की साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन में नवाचार, स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देने वाले साईन बोर्डों आदि जैसे आवश्यक पहलुओं को शामिल करते हुए अलग-अलग स्थलों पर हां/नहीं उत्तर वाले पैरामीटर शामिल हैं।

भाग लेने के इच्छुक अलग-अलग ASI स्मारकों को 10 दिनों के भीतर चेकलिस्ट भरना आवश्यक थी। इसके बाद उन स्मारकों/स्थलों के रख-रखाव का आकलन करने के लिए नामित टीमों द्वारा दौरा किया जाएगा। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दो स्थलों/स्मारकों को विजेता घोषित किया जाएगा और उन्हें स्वच्छ पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी जाएगी और सम्मानित किया जाएगा।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

गुजरात में स्वच्छता चैंपियन बन रही हैं SHG महिलाएं

गुजरात जैसे प्रगतिशील राज्य में, स्वच्छता ही सेवा (SHS) 2023 अभियान के बैनर तले, जिसे 15 सितंबर से 15 दिसंबर 2023 तक लागू किया जा रहा है, स्वयं सहायता समूहों (SHG) की 17,425 महिलाओं को स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता के चैंपियन में बदलने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण के नेतृत्व में, SHG की महिलाओं को जागरूकता को बढ़ावा देने, ठोस और तरल कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने और उनके संबंधित समुदायों के भीतर अलगाव शेड के संचालन की देखरेख करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी।

प्रशिक्षण सत्रों को तीन मुख्य मॉड्यूल में विभाजित किया गया था: जागरूकता संवर्धन; ठोस और तरल कचरा प्रबंधन; और अलगाव शेड का प्रबंधन - प्रत्येक SHG अभियान के दौरान ODF Plus के विभिन्न घटकों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जैसे-जैसे सप्ताह बीतते गए, 17,425 SHG सदस्य SHS 2023 के चैंपियन में परिवर्तित हो गए। ज्ञान, कौशल और एक अटूट दृढ़ संकल्प से सुसज्जित, वे परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में अपने समुदायों में वापस लौट आए। वे स्वच्छता अभियान आयोजित कर रहे हैं, घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और 4 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने 687 अलगाव शेड के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ली है।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क: zulfiqar.sheth@in.ey.com

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) ने आयोजित किए अंतरराज्यीय एक्सपोजर विजिट

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक्सपोजर विजिट आयोजित कर रहा है ताकि वे अन्य राज्यों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम ODF Plus प्रथाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि वे अपने संबंधित राज्यों में क्षेत्रों के विशिष्ट संशोधनों के साथ इसे अपनाएं।

पिछले कुछ महीनों से DDWS समीक्षा बैठकों, राज्य दौरों और सम्मेलनों के दौरान नियमित अंतराल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बातचीत कर रहा है। इन संवादों के दौरान, यह देखा गया कि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बहुत सारे अनुकरणीय कार्य किए जा रहे हैं, जिन्हें अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा करने की आवश्यकता है।

एक्सपोजर यात्राओं के दौरान, आगंतुकों को मेजबान राज्य द्वारा पालन की जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत कराया जा सकता है, जिससे वे अपने इलाके और अन्य स्थितियों के अनुरूप संशोधनों के साथ अपने गृह राज्य में इसे वापस अपना सकते हैं।

यह कदम न केवल राज्यों को उनकी चुनौतियों को समझने के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक पहल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और इस प्रक्रिया में नई पहल और प्रथाओं का निर्माण करेगा। इसके अलावा, इस कार्य से दौरे पर आने वाले अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि होगी और ज्ञान साझा करने से लाभार्थियों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए SBM-G चरण-2 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

पहली एक्सपोजर यात्रा कर्नाटक में आयोजित की गई थी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने विभिन्न मलीय कीचड़ प्रबंधन (FSM) और ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (SLWM) इकाइयों का अवलोकन किया।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

बिहार को मिले तीन प्रतिष्ठित स्वच्छता पुरस्कार

बिहार ने 2023 के प्रतिष्ठित ISC-FICCI स्वच्छता पुरस्कारों में से 3 जीतकर ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्र में अत्यधिक पहचान हासिल की। राज्य ने स्वच्छता (डिजिटल) में सर्वश्रेष्ठ संचार; लाइटहाउस पहल (LHI) ढांचे के भीतर ODF Plus Model गांवों की सबसे अधिक संख्या और स्वच्छता श्रेणी में महिला चेंजमेकर्स में राज्य के लिए विशेष पहचान के लिए पुरस्कार जीते।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) पुरस्कार समारोह में भारत स्वच्छता गठबंधन (ISC) का 7वां संस्करण 20 और 21 नवंबर, 2023 को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया गया था।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मिशन निदेशक श्री राहुल कुमार और राज्य समन्वयक - श्री राजेश कुमार ने राज्य पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि श्रीमती कोमल मुखिया, हरला ग्राम पंचायत (GP), लक्ष्मीपुर ब्लॉक, जमुई जिले को स्वच्छता श्रेणी में महिला चेंजमेकर्स के लिए पुरस्कार मिला।

बिहार में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम (DCMS) पहल के तहत स्वच्छता और साफ-सफाई से संबंधित संदेश विशेष रूप से शौचालयों के नियमित उपयोग, स्वच्छता की आदतों को अपनाने, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन आदि के बारे में मोबाइल संदेशों के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। यह वर्तमान में 1,563 ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है और यूनिसेफ और विकास प्रबंधन संस्थान, पटना के सहयोग से राज्य के सभी शेष ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित किया जाएगा।

अधिक पढ़ने के लिए, **यहाँ क्लिक करें**

संपर्क: sc.iec@lsba.in

राज्यों के झरोखे से

शिव सिंह मीणा
मिशन निदेशक, ग्रामीण स्वच्छता
RD, PRI और ULB विभाग

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सतत कचरा प्रबंधन

बंगाल की खाड़ी के शांत विस्तार में संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जो नीले समुद्र और जीवंत हरियाली से सजा हुआ है। अपनी अनूठी वनस्पतियों और जीवों का पोषण करते हुए, कचरा प्रबंधन इन द्वीपों के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभर रहा है।

समुदाय संचालित शून्य कचरा लक्ष्य: 70 समर्पित ग्राम पंचायतों के साथ, हम RD निदेशालय, PRI द्वारा समर्थित #ZeroWasteIslands के लक्ष्य को पूरे उत्साह से आगे बढ़ा रहे हैं। इस सहयोगात्मक प्रयास ने ODF Plus और स्वच्छ और सुजल प्रदेश के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए, उन्हें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा यह सम्मान दिया गया।

अभिनव कचरा हैंडलिंग और कानून: ठोस कचरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, 26 क्लस्टर स्थापित किए गए हैं, जो अलग-अलग प्रकार के कचरे की ढुलाई के लिए माल ढुलाई शुल्क से छूट का उपयोग करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पंचायती राज संस्थान और जनजातीय परिषद ठोस अपशिष्ट उप-कानून, 2019 नियमों, दंड और उपयोगकर्ता शुल्क को रेखांकित करता है। विशेष रूप से, 8% कटा हुआ प्लास्टिक सड़क निर्माण में योगदान देता है, जो सरकारी मानदंडों के अनुरूप है।

समग्र तरल एवं ठोस कचरा प्रबंधन: सोख्ता गड्ढे और वर्मीकम्पोस्ट पहल के तहत तरल कचरा प्रबंधन का कार्य करते हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से इसके उत्पादन और बिक्री में शामिल होते हैं। इसके साथ ही, 'कांच संचय' से संबंधित चुनौतियों से निपटने की नवाचार पहल चल रही है।

सामुदायिक जुड़ाव और पर्यावरणीय पहल: पंचायतों से राज्य तक विभिन्न स्तरों पर नियमित जागरूकता शिविर, IEC और BCC पहल और समुद्र तट सफाई अभियान होते हैं। मिशन LiFE और पूरे द्वीपों में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जैसे प्रमुख अभियान चलाते हैं।

समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण: समुद्री जीवन के लिए भविष्य के प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे को पहचानते हुए, संघ राज्य क्षेत्र अपने प्राचीन पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बड़ी लगनता से सकारात्मक राजनीतिक कदम उठाते हुए कार्य कर रहे है। रणनीतिक कदमों और पहलों के माध्यम से, इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित आश्रय सुनिश्चित करना है।

अपशिष्ट प्रबंधन शब्द मिलान

1	अपशिष्ट पदानुक्रम	क	प्लास्टिक
2	अपशिष्ट प्रबंधन 5 रुपये	ख	स्वाभाविक रूप से विघटित या टूटते नहीं हैं।
3	भस्मीकरण	ग	लंबे समय तक चलने वाले जिंसों को डिजाइन करना
4	एक आइटम जिसे आपके कंपोस्ट के कूड़े में नहीं डाला जाना चाहिए	घ	औद्योगिक और अस्पताल का कचरा
5	गैरबायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर्यावरण में एक समस्या है क्योंकि	ङ	गीले कचरे को खाद में बदलना
6	ई-कचरा कहाँ से उत्पन्न होता है?	च	कम करने, पुनः उपयोग करने, रीसाइक्लिंग, रिकवरी और निपटान पर जोर देता है
7	स्रोत में कमी किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है?	छ	बार स्क्रीन
8	खतरनाक कचरा	ज	एक प्रक्रिया जिसमें मिश्रित कचरे को बहुत अधिक तापमान पर जलाया जाता है
9	खाद	झ	इलेक्ट्रॉनिक्स
10	अपशिष्ट जल उपचार के दौरान, प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे और अन्य बड़ी वस्तुओं को किसके द्वारा हटाया जाता है?	ट	रिफ्यूज, रिड्यूज, रियुज पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना

उत्तर: 1-च, 2-ट, 3-ज, 4-क, 5-ख, 6-झ, 7-ग, 8-घ, 9-ङ, 10-छ

सचिव की कलम से

श्रीमती विनी महाजन
सचीव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय

इस नये वर्ष, जैसा कि हम भारत के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को ODF Plus बनाने के लक्ष्य की तरफ और अधिक निकट हैं, हम यह स्वीकार करते हैं कि मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और साफ-सफाई अत्यंत आवश्यक है। SBM-G ने वास्तविक तौर पर सुरक्षा, सम्मान और जीवन-यापन के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति योगदान दिया है। आने वाले वर्ष में, हमारे लगभग 6 लाख गांवों को सार्वभौमिक स्वच्छता के अंतिम लक्ष्य के अंतर्गत कवर करने हेतु हम मार्ग में खड़ी सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढेंगे, साथ हीं उन्हें प्राथमिकता देंगे,जिन्हें इसकी सवार्धिक आवश्यकता है। नव वर्ष की शुभकामनाएं!

मिशन निदेशक की कलम से

श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM-G)
डीडीडब्ल्यूएस, जल शक्ति मंत्रालय

ODF Plus गतिविधियों की दृष्टि से 2023 एक पूर्णत: उल्लेखनीय वर्ष रहा। जैसा कि ग्रामीण भारत में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन एक नियमित विशेषता बन चुकी है, इस संदर्भ में SBM-G का चरण-II के लिए यह वर्ष सर्वाधिक उपयुक्त रहा है। जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार, लगभग 1.36 लाख (25%) ODF Plus गांव थे तथा 29 दिसंबर 2023 तक इस संख्या में तीव्र वृद्धि हुई और 5 लाख (83%) से भी अधिक गांवों ने स्वयं को ODF Plus घोषित किया। SBM-G के उन सभी सह-कर्मियों का बहुत आभार जिन्होंने देश में स्वच्छता लाने हेतु समर्पण भाव से अपनी सहायता निरंतर रूप से प्रदान की।

To contribute to the next issue of the **Swachhata Samachar,**
share your submission before the 15th of every month to swachhbharat@gov.in.

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

Office of the Joint Secretary & Mission Director, SBM-G
Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shak
Government of India.
4th Floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone: 011-24362192 | Email: js-sbm@gov.in